



ISSN: 2395-7852



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 5, September 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462

+91 9940572462

ijarasem@gmail.com

www.ijarasem.com

निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षको की शिक्षण अभियोग्यता, क्रिया आधारित शिक्षण, एवं व्यवसायिक मूल्यों का अध्ययन

NISHTHA: National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement

Fakhre Alam

Assistant Professor, Department of Education, H.R.P.G. College, Khalilabad, Sant Kabir Nagar,

Uttar Pradesh, India

सार

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन 'नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा)' लॉन्च किया है।

▪ मंत्री द्वारा निष्ठा वेबसाइट, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्राइमर बुकलेट और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।

'स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल' के बारे में

- निष्ठा दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- उद्देश्य: छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना।
- शिक्षकों को इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता मिलेगी और उनका कौशल विकसित होगा:

- सीखने के परिणाम,
- योग्यता-आधारित शिक्षा और परीक्षण,
- शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र,
- स्कूल सुरक्षा और संरक्षा,
- व्यक्तिगत-सामाजिक गुण,
- समावेशी शिक्षा,
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित शिक्षण-अधिगम में आईसीटी,
- योग सहित स्वास्थ्य एवं खुशहाली,
- पुस्तकालय, इको-क्लब, युवा क्लब, किचन गार्डन सहित स्कूली शिक्षा में पहल
- स्कूल नेतृत्व गुण,
- पर्यावरणीय चिंता,
- प्री-स्कूल, प्री-व्यावसायिक शिक्षा और स्कूल-आधारित मूल्यांकन।

परिचय

- उद्देश्य: लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना ,
 - सभी सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को कवर करना,
 - राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के संकाय सदस्य,
 - सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक।
- कार्यान्वयन: प्रशिक्षण राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए 33120 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (केआरपी) और राज्य संसाधन व्यक्तियों (एसआरपी) द्वारा सीधे आयोजित किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से पहचाने गए 120 राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), आदि।
 - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास निष्ठा के मुख्य विषयों और अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रासंगिक बनाने और अपनी स्वयं की सामग्री और संसाधन व्यक्तियों का भी उपयोग करने का विकल्प है।
 - कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं गतिविधि आधारित मॉड्यूल हैं जिनमें अंतर्निहित निरंतर फीडबैक तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रभाव विश्लेषण (प्रशिक्षण से पहले और बाद में) शामिल हैं।
- NCERT द्वारा MOODLE (मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट) पर आधारित एक मोबाइल ऐप और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) विकसित किया गया है।[1,2]
 - एलएमएस का उपयोग संसाधन व्यक्तियों और शिक्षकों के पंजीकरण, संसाधनों के प्रसार, प्रशिक्षण अंतराल और प्रभाव विश्लेषण, निगरानी, सलाह और प्रगति को ऑनलाइन मापने के लिए किया जाएगा।

शिक्षा सामाजिक प्रगति, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और राष्ट्रों को आकार देने की आधारशिला है। भारत के मामले में, एक विशाल और विविध आबादी वाला देश, शिक्षा की गुणवत्ता समावेशी विकास, नवाचार और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में सराहनीय प्रगति के बावजूद, पूरे बोर्ड में शिक्षा के उच्च मानक को सुनिश्चित करना लगातार चुनौती बनी हुई है।

वर्तमान लेख भारत में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के महत्व की पड़ताल करता है और इसकी प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल सूचना के प्रसार तक ही सीमित नहीं है। इसमें आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या-समाधान कौशल और चरित्र निर्माण का विकास शामिल है। यह व्यक्तियों को जटिल चुनौतियों पर सवाल उठाने, विश्लेषण करने और समाधान खोजने का अधिकार देता है, और उन्हें सक्रिय सामाजिक योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार करता है। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

- पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक अनिवार्य घटक एक मजबूत पाठ्यक्रम तैयार करना है जो सीखने के लिए एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। पाठ्यक्रम को अंतःविषय सोच, रचनात्मकता और वास्तविक दुनिया में प्रयोज्यता को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षार्थी-केंद्रित शैक्षणिक प्रथाओं को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो सक्रिय भागीदारी, पूछताछ-आधारित शिक्षा और व्यावहारिक कौशल के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- शिक्षक सशक्तिकरण और व्यावसायिक विकास: शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। उनका सशक्तिकरण और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसमें योग्य और प्रेरित शिक्षकों की भर्ती करना, निरंतर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना और ज्ञान के सुविधा प्रदाता के रूप में उनकी वृद्धि का समर्थन करना शामिल है। शिक्षकों के

बीच नवाचार, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की उनकी क्षमता बढ़ती है।

- बुनियादी ढाँचा और सीखने का माहौल: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुकूल सीखने का माहौल अपरिहार्य है। अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सहित पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, एक आकर्षक और समृद्ध सीखने के अनुभव को बढ़ावा दे सकता है। एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण जो सहयोग, विविधता और सम्मान को प्रोत्साहित करता है, समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र: एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली पारंपरिक परीक्षाओं से परे जाती है और व्यापक मूल्यांकन विधियों को अपनाती है जो छात्रों की समझ, अनुप्रयोग और महत्वपूर्ण सोच कौशल का आकलन करती है। नियमित फीडबैक लूप शिक्षकों को ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और तदनुसार शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है।[3,5]
- समानता और समावेशन: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना, लैंगिक असमानताओं को कम करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को संबोधित करना आवश्यक है। वंचित छात्रों के लिए पर्याप्त संसाधन, छात्रवृत्ति और सहायता प्रणाली प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खोज इसकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक सशक्तिकरण, बुनियादी ढाँचे का विकास, समावेशी अभ्यास और मजबूत मूल्यांकन प्रणाली शामिल हो। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सहयोग करना चाहिए। अपने नागरिकों की बौद्धिक पूंजी में निवेश करके, भारत अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्वल भविष्य सुरक्षित कर सकता है।

नीचे, हम विभिन्न पहलुओं से भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करते हैं:

भारत में सामान्य रूप से शिक्षा और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार विभिन्न स्तरों पर चल रहा है, जिसमें सरकारी पहल, नीति सुधार और कई हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं।

यहां कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं जिन्हें हाल के दिनों में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020): एनईपी 2020 एक व्यापक नीति ढाँचा है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलना है। यह समग्र और बहु-विषयक शिक्षा पर जोर देता है, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह नीति शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और रटने पर जोर कम करने पर भी केंद्रित है।
2. शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास: शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं। निष्ठा: स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को नए शैक्षणिक दृष्टिकोण, सामग्री ज्ञान और कक्षा प्रबंधन कौशल के साथ प्रशिक्षित और सशक्त बनाना है।
3. सीखने के परिणाम और मूल्यांकन: ध्यान रटकर याद करने और परीक्षाओं से हटकर सीखने के परिणामों को मापने पर केंद्रित हो गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करते हैं, जिससे शिक्षकों को अंतराल की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेप लागू करने की अनुमति मिलती है। ये आकलन शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार में मदद करते हैं।[7,8]
4. प्रौद्योगिकी एकीकरण: सरकार ने सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्रोत्साहित किया है। डिजिटल इंडिया अभियान, स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-पाठशाला डिजिटल संसाधन जैसी पहल शैक्षिक सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच प्रदान करती हैं। डिजिटल उपकरणों और संसाधनों का उपयोग इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को सक्षम बनाता है।
5. बुनियादी ढाँचा विकास: अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए बुनियादी ढाँचा विकास एक फोकस क्षेत्र रहा है। सरकार ने कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण सहित स्कूल के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।
6. सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सरकार, गैर-लाभकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की पहल से जुड़े सहयोगात्मक प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक रहे हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और संसाधन-साझाकरण को अपनाने की सुविधा प्रदान की है।

7. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास : व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए, छात्रों को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी पहल शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटने, छात्रों को विभिन्न कैरियर पथों के लिए व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

ऊपर सुझाए गए उपाय संपूर्ण नहीं हैं। चुनौतियों का समाधान करने और सभी शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन, नीति सुधार और हितधारक सहयोग महत्वपूर्ण हैं।

विचार-विमर्श

भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसकी प्रभावशीलता और प्रभाव में बाधक हैं। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य मुद्दे शामिल हैं:

- रटकर सीखने की संस्कृति: कई स्कूलों में रटकर याद करने और परीक्षा-उन्मुख सीखने के तरीकों पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण अक्सर छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान कौशल और रचनात्मकता के विकास में बाधा डालता है।
- पुराना पाठ्यक्रम: कई शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम अक्सर पुराना हो चुका है और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से कटा हुआ है। यह आधुनिक कार्यबल की उभरती जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकता है या विषयों की समग्र समझ को बढ़ावा नहीं दे सकता है।
- योग्य शिक्षकों की कमी: कई स्कूलों में, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, योग्य और अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। अपर्याप्त भर्ती और प्रतिधारण प्रथाएं, साथ ही अपर्याप्त व्यावसायिक विकास के अवसर, इस मुद्दे में योगदान करते हैं।
- बुनियादी ढाँचा और संसाधन अंतराल: कई स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण स्कूलों में, उचित कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं जैसे बुनियादी ढाँचे का अभाव है। प्रौद्योगिकी और सीखने के संसाधनों तक सीमित पहुंच गुणवत्ता के अंतर को और बढ़ा देती है।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में असमानताएँ पैदा करती हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों, कम आय वाली पृष्ठभूमि और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने और उससे लाभ उठाने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है [9,10]।
- मूल्यांकन प्रणाली: परीक्षा-केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली अक्सर गहरी समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग के बजाय रटने को प्रोत्साहित करती है। विविध कौशलों और दक्षताओं को मापने के लिए व्यापक मूल्यांकन विधियों की कमी चुनौतीपूर्ण है।
- शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास: शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों पर अपर्याप्त जोर शिक्षकों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की क्षमता में बाधा डालता है। निरंतर सीखने और कौशल उन्नयन के सीमित अवसर बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने की उनकी क्षमता को सीमित कर देते हैं।
- लैंगिक असमानताएँ: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच में लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और भेदभावपूर्ण रवैया लड़कियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण दर को कम करने में योगदान करते हैं, जिससे शिक्षा की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- समग्र विकास पर फोकस की कमी : शैक्षणिक प्रदर्शन पर जोर अक्सर शारीरिक शिक्षा, कला और पाठ्येतर गतिविधियों सहित समग्र विकास को दरकिनार कर देता है। छात्रों के समग्र विकास और कल्याण की उपेक्षा करने से जीवन के विभिन्न पहलुओं में आगे बढ़ने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
- अपर्याप्त शिक्षा नीतियाँ और शासन: नीति कार्यान्वयन अंतराल, नौकरशाही अक्षमताएँ, और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की कमी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में बाधा डालती है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए नीति निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, समुदायों और अन्य हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे के विकास, मूल्यांकन प्रथाओं और शिक्षा तक समान पहुंच में सुधार महत्वपूर्ण हैं।

समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण चल रहे कार्यक्रमों में से एक है। समग्र शिक्षा ने पिछले सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एक व्यापक कार्यक्रम में एकीकृत किया, जिसका नाम समग्र शिक्षा रखा गया और इसे 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित घटक हैं:

1. पाठ्यचर्या विकास और संशोधन: समग्र शिक्षा विकास और संशोधन पर जोर देती है। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और कौशल विकास को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।

2. शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम: यह कार्यक्रम छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण संवर्धन कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित है। सीखने की कमियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र वांछित शैक्षिक मानकों को प्राप्त कर सकें, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त कोचिंग और सहायता प्रदान की जाती है।
3. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: समग्र शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और निरंतर सीखने के अवसरों के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर जोर देती है। इससे उनके शैक्षणिक कौशल, विषय ज्ञान और नवीन शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे अंततः शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होता है।[11,12]
4. गुणवत्ता मूल्यांकन और निगरानी: कार्यक्रम सीखने के परिणामों को मापने और शैक्षिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन उपकरणों और प्रक्रियाओं के विकास पर जोर देता है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, प्रगति पर नज़र रखने और शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए नियमित मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं।
5. शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग: समग्र शिक्षा शिक्षण और सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने को बढ़ावा देती है। यह इंटरैक्टिव और वैयक्तिकृत शिक्षण को सक्षम करते हुए डिजिटल संसाधन, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और आईसीटी-सक्षम कक्षाएँ प्रदान करने का समर्थन करता है।
6. अनुसंधान एवं नवाचार: कार्यक्रम सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप विकसित करने और शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। यह विचारों और प्रभावी प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए अनुसंधान अध्ययन, पायलट परियोजनाओं और ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्मों का समर्थन करता है।
7. सामुदायिक भागीदारी और स्कूल प्रबंधन समितियाँ: समग्र शिक्षा स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन करके स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। एसएमसी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में माता-पिता, समुदाय के सदस्यों और हितधारकों को शामिल करते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलता है।

इन पहलुओं को संबोधित करके, समग्र शिक्षा का लक्ष्य पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी एकीकरण, अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ये पहल सामूहिक रूप से भारत में छात्रों के लिए समग्र शैक्षिक गुणवत्ता और परिणामों में सुधार करती हैं।

भारत में सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता अलग-अलग है, और कुछ उल्लेखनीय अंतर हैं, जिन पर विचार करने के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:

सरकारी स्कूल

1. सामर्थ्य और पहुंच: सरकारी स्कूल आम तौर पर अधिक किफायती या निःशुल्क होते हैं, जिससे वे आबादी के अधिक महत्वपूर्ण वर्ग, विशेष रूप से निम्न-आय पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए सुलभ हो जाते हैं।
2. बुनियादी ढाँचा: सरकारी स्कूलों को अक्सर अपर्याप्त कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और स्वच्छता सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचे के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी पहल की जा रही हैं।
3. शिक्षक गुणवत्ता: हालाँकि सरकारी स्कूलों में कई समर्पित और सक्षम शिक्षक हैं, लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी है, और कुछ स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता अलग-अलग स्कूलों में भिन्न हो सकती है।[1,2]
4. पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र: सरकारी स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। हालाँकि, मानकीकृत दृष्टिकोण के कारण, नवाचार, लचीलेपन और ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के मामले में सीमाएँ हैं।
5. सामुदायिक भागीदारी: सरकारी स्कूलों का अक्सर स्थानीय समुदाय के साथ मजबूत संबंध होता है और उनसे विविध छात्र आबादी को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। इससे समावेशिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है।

निजी स्कूल

1. बुनियादी ढाँचा और संसाधन: निजी स्कूलों में आम तौर पर बेहतर बुनियादी ढाँचा होता है, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और खेल सुविधाएँ शामिल हैं। उनके पास अक्सर उन संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच होती है जो आधुनिक शिक्षण विधियों का समर्थन करते हैं।
2. शिक्षक गुणवत्ता: निजी स्कूलों में आमतौर पर शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए एक कठोर चयन प्रक्रिया होती है और वे बेहतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षण की उच्च गुणवत्ता और छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है।

3. पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र: निजी स्कूलों में अक्सर पाठ्यक्रम डिजाइन में अधिक लचीलापन होता है, जिससे नवीन शिक्षण विधियों और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। वे अतिरिक्त विषय, विदेशी भाषा कार्यक्रम या विशेष पाठ्यक्रम पेश कर सकते हैं।
4. माता-पिता की भागीदारी: निजी स्कूलों में स्कूल की गतिविधियों, प्रशासन और निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी के साथ, माता-पिता की भागीदारी का उच्च स्तर होता है। यह माता-पिता और स्कूल के बीच मजबूत साझेदारी में योगदान दे सकता है।
5. शुल्क संरचना: निजी स्कूल शुल्क लेते हैं, और वे संस्थान, स्थान और दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर काफी भिन्न हो सकते हैं। इससे निम्न-आय पृष्ठभूमि वाले परिवारों की पहुंच सीमित हो सकती है।[12,13]

ऊपर प्रस्तुत बिंदु प्रकृति में सामान्य अवलोकन हैं, और सरकारी और निजी स्कूलों में भिन्नताएं हैं। शिक्षा की गुणवत्ता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें व्यक्तिगत स्कूलों का प्रबंधन, शिक्षकों की प्रतिबद्धता, सामुदायिक भागीदारी और शैक्षिक नीतियों और विनियमों का कार्यान्वयन शामिल है।

कई कारणों से सरकारी स्कूलों की तुलना में शिक्षकों को कम वेतन देने के बावजूद निजी स्कूलों की गुणवत्ता अक्सर बेहतर होती है:

1. चयन और योग्यता-आधारित नियुक्ति: निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अक्सर एक कठोर चयन प्रक्रिया होती है। वे योग्यता-आधारित नियुक्ति को प्राथमिकता देते हैं, अपने विषयों में विशेषज्ञता वाले उच्च योग्य और सक्षम व्यक्तियों की तलाश करते हैं। सर्वोत्तम उम्मीदवारों के चयन पर यह ध्यान निजी स्कूलों में शिक्षण की समग्र गुणवत्ता में योगदान देता है।
2. व्यावसायिक विकास के अवसर: निजी स्कूल शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के महत्व को पहचानते हैं। वे अक्सर शिक्षकों के शैक्षणिक कौशल, विषय ज्ञान और शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करने में निवेश करते हैं। व्यावसायिक विकास में यह निवेश शिक्षकों को उनकी शिक्षण क्षमताओं में सुधार करने और नवीनतम शैक्षिक प्रथाओं के साथ बने रहने में मदद करता है।
3. जवाबदेही और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: निजी स्कूल प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करते हैं और माता-पिता और छात्रों के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे छात्रों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। निजी स्कूल शिक्षकों को उनके वेतन वृद्धि या बोनस को उनके प्रदर्शन से जोड़कर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, जो शिक्षकों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर सकता है।[1]
4. छोटी कक्षा का आकार: निजी स्कूलों में अक्सर सरकारी स्कूलों की तुलना में कक्षा का आकार छोटा होता है। यह शिक्षकों को प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने और एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाने की अनुमति देता है। छोटी कक्षा का आकार बेहतर छात्र-शिक्षक बातचीत की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्रदर्शन और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।
5. पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में लचीलापन: निजी स्कूलों में अक्सर पाठ्यक्रम डिजाइन करने और नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने में अधिक लचीलापन होता है। वे अपने छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं, आधुनिक शिक्षण तकनीकों को पेश कर सकते हैं और अनुभवात्मक सीखने के अवसरों को शामिल कर सकते हैं। यह लचीलापन उन्हें शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाते हुए अधिक गतिशील और आकर्षक शिक्षण अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
6. माता-पिता की ठोस भागीदारी और समर्थन: निजी स्कूलों में अक्सर सक्रिय और शामिल माता-पिता होते हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। माता-पिता का यह समर्थन, जिसमें उनकी अपेक्षाएं और स्कूल की गतिविधियों में भागीदारी शामिल है, सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बना सकता है और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है।

हालांकि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में कम वेतन दे सकते हैं, लेकिन शिक्षकों के चयन, पेशेवर विकास, जवाबदेही, छोटे वर्ग के आकार, लचीले पाठ्यक्रम और मजबूत माता-पिता की भागीदारी पर उनका ध्यान सामूहिक रूप से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देता है।

परिणाम

सरकारी स्कूलों में शिक्षक चयन प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक प्राधिकरणों में भिन्न हो सकती है। हालांकि सरकारी स्कूलों में समर्पित और सक्षम शिक्षक हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया हमेशा निजी स्कूलों की तरह कठोर नहीं हो सकती है। बड़ी संख्या में रिक्तियां, नौकरशाही प्रक्रियाएं और सीमित संसाधन जैसे कारक कभी-कभी चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया में आमतौर पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धी परीक्षा या पात्रता मानदंड शामिल होते हैं। हालाँकि, सरकारी स्कूलों में शिक्षण पदों की उच्च मांग के कारण, चयन प्रक्रिया में हमेशा योग्यता-आधारित नियुक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है या निजी स्कूलों की तरह व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कूल के शिक्षकों, विशेष रूप से संविदा शिक्षकों को दिए जाने वाले मुआवजे और लाभ पैकेज अलग-अलग हो सकते हैं, और कुछ मामलों में, वे निजी स्कूलों की तुलना में कम हो सकते हैं। यह सरकारी स्कूलों में शिक्षण पदों के आकर्षण को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे आवेदकों की समग्र गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।[1,2]

यह भी एक तथ्य है कि सरकारी स्कूलों में कई उच्च योग्य और समर्पित शिक्षक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए शिक्षक चयन प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक विकास के अवसरों को बढ़ाने और सरकारी स्कूलों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हां, भारत में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, खासकर सरकारी स्कूलों और विशेष रूप से दूरदराज या आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में। शिक्षकों की कमी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र-शिक्षक अनुपात को प्रभावित कर सकती है। शिक्षकों की कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं:

1. अपर्याप्त भर्ती: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं हो सकती है। भर्ती में देरी, नौकरशाही प्रक्रियाओं और बजट की कमी के कारण शिक्षकों की कमी हो सकती है।
2. असमान वितरण: शिक्षकों की तैनाती में अक्सर असंतुलन होता है, कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों की अधिकता होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी होती है। शहरी क्षेत्र और अधिक आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र अधिक शिक्षकों को आकर्षित करते हैं, जबकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कम योग्य शिक्षक रह जाते हैं।
3. नौकरी छोड़ने और बनाए रखना: उच्च नौकरी छोड़ने की दर और शिक्षकों को बनाए रखने में चुनौतियाँ कमी को और बढ़ा देती हैं। कम वेतन, सीमित कैरियर विकास के अवसर, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और कठिन कामकाजी परिस्थितियाँ जैसे कारक शिक्षकों को पेशे में बने रहने या कुछ क्षेत्रों में पद स्वीकार करने से हतोत्साहित कर सकते हैं।
4. योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक: गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में पर्याप्त संख्या में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। विषय-विशेष शिक्षकों की कमी उन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षकों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है। कुछ उपाय जो उठाए जा सकते हैं उनमें शामिल हैं:

1. भर्ती और प्रशिक्षण: भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, समय पर भर्ती अभियान चलाना और योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए कठोर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
2. प्रोत्साहन और सहायता: शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन, लाभ और कैरियर में उन्नति के अवसर प्रदान करना। दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक शिक्षकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से भौगोलिक असंतुलन को दूर करने में मदद मिल सकती है।
3. शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास: शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के महत्व पर जोर देना और उनके शैक्षणिक कौशल और विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना। यह कक्षा में उनकी प्रभावशीलता में योगदान दे सकता है।
4. समान तैनाती : ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी क्षेत्रों में शिक्षकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को लागू करना। आवास सुविधाएं, परिवहन और अन्य सहायता प्रणाली जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने से इन क्षेत्रों को शिक्षकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
5. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण प्लेटफार्मों और आभासी कक्षाओं का उपयोग करने से विषय-विशिष्ट शिक्षकों की कमी को दूर करने और दूरदराज के क्षेत्रों में भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

शिक्षकों की कमी को दूर करने और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती में सुधार के लिए सरकार और शैक्षिक अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि, यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है जिस पर निरंतर ध्यान देने और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

हां, अयोग्य शिक्षकों की मौजूदगी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। योग्य शिक्षकों के पास प्रभावी ढंग से निर्देश देने, सीखने की सुविधा प्रदान करने और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण होता है। जब अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, तो इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं:

- विषय विशेषज्ञता की कमी: अयोग्य शिक्षकों के पास जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों को गलत या अधूरी जानकारी दी जा सकती है, जिससे उनकी समझ सीमित हो सकती है और उनकी शैक्षणिक प्रगति में बाधा आ सकती है।
- अप्रभावी शिक्षण पद्धतियाँ: योग्य शिक्षकों को शैक्षणिक तकनीकों और निर्देशात्मक रणनीतियों में प्रशिक्षित किया जाता है जो प्रभावी शिक्षण को बढ़ावा देते हैं। अयोग्य शिक्षकों को उचित शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की कमी हो सकती है, जिससे छात्रों के लिए कम आकर्षक और कम प्रभावी कक्षा अनुभव हो सकता है।
- अपर्याप्त कक्षा प्रबंधन: अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए योग्य शिक्षक कक्षा प्रबंधन कौशल से लैस होते हैं। अयोग्य शिक्षकों को अनुशासन बनाए रखने, छात्रों के व्यवहार को प्रबंधित करने और कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जो सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं की सीमित समझ: योग्य शिक्षकों को छात्रों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पहचानने और संबोधित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित कर सकते हैं। अयोग्य शिक्षकों में व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए समझ और कौशल की कमी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण हो सकता है जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है। [2,3]
- मूल्यांकन और परीक्षाओं पर प्रभाव: अयोग्य शिक्षक मूल्यांकन दिशानिर्देशों और परीक्षा पैटर्न से परिचित नहीं हो सकते हैं, जो संभावित रूप से मूल्यांकन की सटीकता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसके छात्रों के शैक्षिक अवसरों और संभावनाओं पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्कूलों में सभी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता और मानकों को पूरा करें। सरकारों, शैक्षिक अधिकारियों और संस्थानों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को योग्य और सक्षम शिक्षकों से शिक्षा मिले।

सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षक बहुत हैं।

भारत में सरकारी स्कूलों में अलग-अलग राज्यों में कई संविदा शिक्षक हैं। संविदा शिक्षकों को एक विशिष्ट अवधि या परियोजना के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, अक्सर नियमित या स्थायी शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए। उन्हें स्कूलों में, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों या योग्य शिक्षकों की कमी वाले विषयों में तत्काल स्टाफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिए गए हैं:

- अस्थायी अनुबंध: संविदा शिक्षक स्कूल की आवश्यकताओं और शिक्षक के प्रदर्शन के आधार पर अस्थायी अनुबंधों के तहत काम करते हैं, जो आमतौर पर नवीकरणीय होते हैं।
- योग्यता और पात्रता: संविदा शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट न्यूनतम योग्यता और पात्रता मानदंडों को पूरा करें। हालाँकि, योग्यता आवश्यकताएँ राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
- नौकरी की सुरक्षा: स्थायी शिक्षकों की तुलना में, संविदा शिक्षकों को अक्सर नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका रोजगार धन की उपलब्धता, परियोजना अवधि या विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर होता है। उनके अनुबंध नियमित शिक्षकों के समान नौकरी की स्थिरता और लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- विभिन्न भूमिकाएँ: संविदा शिक्षकों को आम तौर पर शिक्षण कर्तव्य सौंपे जाते हैं, लेकिन वे अतिरिक्त जिम्मेदारियों में भी शामिल हो सकते हैं जैसे परीक्षा निरीक्षण, प्रशासनिक कार्य, या विभिन्न क्षमताओं में नियमित शिक्षकों का समर्थन करना।
- व्यावसायिक विकास: नियमित शिक्षकों की तुलना में संविदा शिक्षकों के पास व्यावसायिक विकास के अवसरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच हो सकती है। हालाँकि, संविदा शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल और विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। [3,4]
- शिक्षा गुणवत्ता पर प्रभाव: संविदा शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हालाँकि वे शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्रों की शिक्षा तक पहुंच हो, उनकी सीमित नौकरी सुरक्षा और संभावित रूप से कम वेतन उनकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर समग्र प्रभाव संविदा शिक्षकों को प्रदान की गई योग्यता, समर्पण और समर्थन के आधार पर भिन्न हो सकता है।

सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षकों का उपयोग करना शिक्षकों की कमी और संसाधन की कमी की चुनौतियों का जवाब है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और योग्य व्यक्तियों को शिक्षण पेशे में आकर्षित करने के लिए उनके रोजगार के साथ पर्याप्त समर्थन, व्यावसायिक विकास के अवसर और उचित पारिश्रमिक भी हो।

गैर-शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों की भूमिका का शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। यहां विचार करने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

- प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ: शिक्षकों को अक्सर प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं जैसे रिकॉर्ड रखना, स्कूल कार्यक्रमों का आयोजन करना और छात्र-संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करना। हालाँकि ये गतिविधियाँ स्कूल के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक हैं, अत्यधिक प्रशासनिक कर्तव्य शिक्षकों के समय और ध्यान को शिक्षक के रूप में उनकी प्राथमिक भूमिका से भटका सकते हैं।
- पाठ्यचर्या विकास: शिक्षक पाठ्यक्रम विकास, पाठ योजना तैयार करने और शैक्षिक सामग्री बनाने में शामिल हो सकते हैं। उनका इनपुट यह सुनिश्चित करने में मूल्यवान है कि पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप है, सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है और नवीन शिक्षण पद्धतियों को शामिल करता है।
- मूल्यांकन और मूल्यांकन: शिक्षक छात्र प्रगति का आकलन करने, परीक्षा आयोजित करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मूल्यांकन डिजाइन और प्रशासित करते हैं, छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, और परिणामों का उपयोग सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और तदनुसार निर्देश तैयार करने के लिए करते हैं।
- पाठ्येतर और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ: शिक्षक अक्सर खेल आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्लबों जैसी पाठ्येतर और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन और पर्यवेक्षण में भाग लेते हैं। ये गतिविधियाँ छात्रों के समग्र विकास में योगदान देती हैं और उनकी प्रतिभा और रुचियों को बढ़ावा देती हैं।
- माता-पिता की सहभागिता: शिक्षक छात्रों की प्रगति के बारे में संवाद करने, चिंताओं पर चर्चा करने और एक सहायक साझेदारी बनाने के लिए माता-पिता और अभिभावकों के साथ जुड़ते हैं। यह सहयोग छात्र कल्याण को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और घरेलू वातावरण में शिक्षा के महत्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। [4,5]

जबकि गैर-शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों की भागीदारी आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है कि उनका प्राथमिक ध्यान प्रभावी शिक्षण और छात्र सीखने पर बना रहे। अत्यधिक गैर-शिक्षण जिम्मेदारियाँ कार्यभार और समय की कमी को बढ़ा सकती हैं, जो संभावित रूप से कक्षा निर्देश की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने और शिक्षण गुणवत्ता से समझौता किए बिना शिक्षकों को गैर-शिक्षण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए पर्याप्त समय आवंटित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जिम्मेदारियों के आवंटन को अनुकूलित करने और शिक्षकों और छात्रों के लिए अनुकूल सीखने का माहौल बनाने के लिए स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के बीच सहयोग आवश्यक है।

"संतोषजनक गुणवत्ता" शिक्षा के उस स्तर को संदर्भित करता है जो शैक्षिक अधिकारियों, नीति निर्माताओं और समाज द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा छात्रों के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षता हासिल करने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

स्कूली शिक्षा में संतोषजनक गुणवत्ता की अवधारणा में कई पहलू शामिल हैं:

- पाठ्यचर्या: एक अच्छी गुणवत्ता वाला पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को एक सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित प्रमुख विषय और विषय शामिल हों। यह व्यापक, आयु-उपयुक्त और शैक्षिक मानकों और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
- शिक्षण और सीखना: शिक्षा में संतोषजनक गुणवत्ता के लिए सक्षम और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को अपनाते हैं, छात्रों को सक्रिय रूप से संलग्न करते हैं और सार्थक शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं। शिक्षकों को अपने विषयों को गहराई से समझना चाहिए, उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए और आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देना चाहिए।
- बुनियादी ढाँचा और संसाधन : स्कूलों को प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं, संसाधनों और सामग्रियों के साथ एक सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसमें कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, प्रौद्योगिकी और पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ सामग्री और डिजिटल उपकरण जैसे शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच शामिल है।
- छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन: संतोषजनक गुणवत्ता वाली शिक्षा में निष्पक्ष और विश्वसनीय मूल्यांकन और छात्र प्रगति का मूल्यांकन शामिल है। मूल्यांकन को सीखने के उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए और निर्देशात्मक प्रथाओं की जानकारी देनी चाहिए। मूल्यांकन के तरीके पारदर्शी, मानकीकृत और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होने चाहिए। [5,6]

- छात्र सहायता और कल्याण : स्कूलों को छात्रों के समग्र विकास और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें परामर्श, विशेष शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियाँ जैसी सहायता सेवाएँ प्रदान करना शामिल है जो शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती हैं।
- जवाबदेही और निगरानी: संतोषजनक गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए जवाबदेही और निरंतर सुधार के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। शैक्षिक अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को मूल्यांकन, निरीक्षण और फीडबैक तंत्र के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। उन्हें कमियों को दूर करने और निरंतर गुणवत्ता वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

संक्षेप में, स्कूली शिक्षा में संतोषजनक गुणवत्ता का तात्पर्य यह है कि स्कूल एक अच्छी तरह से संरचित पाठ्यक्रम, प्रभावी शिक्षण, पर्याप्त संसाधन, उचित मूल्यांकन, छात्र सहायता और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्धता प्रदान करते हैं।

यह पहचानना आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जबकि सरकारी स्कूल अक्सर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की एक बड़ी संख्या को पूरा करते हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जो उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने में सक्षम बनाए।

सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं:

1. पर्याप्त फंडिंग: सरकारी स्कूलों को अनुकूल शिक्षण माहौल में योगदान देने वाले बुनियादी ढांचे, शिक्षण सामग्री, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों में निवेश करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन अंतराल को पाटने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धन आवंटन आवश्यक है।
2. कुशल और योग्य शिक्षक: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुशल और योग्य शिक्षकों की भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूलों को शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन बनाना चाहिए। कठोर शिक्षक चयन प्रक्रियाएँ और व्यावसायिक विकास के लिए निरंतर समर्थन शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
3. पाठ्यचर्या विकास: एक ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करना जो प्रासंगिक, व्यापक और राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों के अनुरूप हो, आवश्यक है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करे।
4. बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ: सरकारी स्कूलों में प्रभावी शिक्षण और सीखने का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और अन्य आवश्यक सुविधाएँ होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुरक्षित और अनुकूल भौतिक वातावरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
5. सहायता सेवाएँ: परामर्श, विशेष शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियाँ जैसी सहायता सेवाएँ प्रदान करना, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देता है। ये सेवाएँ एक सर्वांगीण शैक्षिक अनुभव में योगदान करती हैं।
6. सामुदायिक सहभागिता: शिक्षा प्रक्रिया में माता-पिता, समुदाय के सदस्यों और अन्य हितधारकों को शामिल करने से एक सहयोगात्मक वातावरण बन सकता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करता है। सक्रिय भागीदारी, संचार और भागीदारी शैक्षिक अनुभव को बढ़ा सकती है।
7. निगरानी और मूल्यांकन: सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन से सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। इसमें मूल्यांकन करना, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से फीडबैक एकत्र करना और निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए डेटा का उपयोग करना शामिल है।

सरकारों, नीति निर्माताओं और समाज को समग्र रूप से सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देने और उसमें निवेश करने की आवश्यकता है, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो छात्रों को सशक्त बनाती है और संसाधन अंतराल को संबोधित करके, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करके और एक सहायक शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करके उनके समग्र विकास और सफलता में योगदान देती है। [6,7]

यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका शिक्षा प्रणाली और छात्रों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नीचे प्रस्तुत कुछ बिंदु शिक्षा की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव डाल सकते हैं:

- सीखने की कमियाँ: शिक्षकों का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना और सीखने की सुविधा प्रदान करना है। जब शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो छात्र आवश्यक निर्देश और शैक्षिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इससे सीखने में महत्वपूर्ण कमियाँ हो सकती हैं और छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में बाधा आ सकती है।

- निम्न शिक्षा गुणवत्ता: सरकारी स्कूलों में शिक्षण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। प्रभावी शिक्षण के बिना, छात्रों को अवधारणाओं को समझने, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और आवश्यक ज्ञान और दक्षता हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
- उपलब्धि अंतर का बढ़ना: जब शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, तो यह मौजूदा शैक्षिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्र जो सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच उपलब्धि का अंतर बढ़ सकता है, जिससे असमानता कायम हो सकती है।
- प्रेरणा और जुड़ाव में कमी: छात्रों को प्रेरित और संलग्न करने के लिए शिक्षण महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, तो छात्र विमुख हो सकते हैं, सीखने में रुचि खो सकते हैं और शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसका उनके शैक्षिक परिणामों और व्यक्तिगत विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
- शिक्षक की जवाबदेही और प्रदर्शन: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका कक्षा में उपस्थिति मात्र से अधिक होती है। शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण निर्देश देने, छात्रों की प्रगति का आकलन करने और मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। जब शिक्षक इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, तो यह शिक्षा प्रणाली के भीतर जवाबदेही और प्रदर्शन प्रबंधन पर सवाल उठाता है।
- बर्बाद संसाधन: सरकारी स्कूल शिक्षकों के वेतन, बुनियादी ढांचे और शैक्षिक सामग्री के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करते हैं। यदि शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण में संलग्न नहीं हैं, तो संसाधनों का कम उपयोग किया जा सकता है या बर्बाद किया जा सकता है, जिससे अक्षमताएं पैदा होंगी और शिक्षा में निवेश पर रिटर्न की कमी होगी।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के न पढ़ाने की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को मजबूत करना, व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना, एक सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना और शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जवाबदेही उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कम शिक्षक मनोबल और सीमित संसाधनों जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षण और सीखने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। [7,8]

भारतीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में माता-पिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे माता-पिता शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देते हैं:

1. सहायक शिक्षण वातावरण: माता-पिता एक निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र, आवश्यक शिक्षण संसाधन और एक नियमित अध्ययन दिनचर्या प्रदान करके घर पर एक सहायक और अनुकूल सीखने का माहौल बना सकते हैं। इससे बच्चों में अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित होती हैं और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
2. सक्रिय भागीदारी: माता-पिता अभिभावक-शिक्षक बैठकों में भाग लेकर, स्कूल की गतिविधियों में भाग लेकर और स्वेच्छा से अपना समय और कौशल देकर अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। उनकी भागीदारी बच्चों को दर्शाती है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है और सीखने के मूल्य को पुष्ट करती है।
3. शिक्षकों के साथ सहयोग: छात्रों के समग्र विकास के लिए माता-पिता और शिक्षकों के बीच प्रभावी संचार और सहयोग आवश्यक है। माता-पिता शिक्षकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रख सकते हैं, अपने बच्चे की प्रगति पर चर्चा कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और शैक्षणिक या व्यवहार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
4. प्रगति की निगरानी: माता-पिता अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसमें होमवर्क की समीक्षा करना, असाइनमेंट में मदद करना और अपने बच्चे के मूल्यांकन प्रदर्शन पर नज़र रखना शामिल है। नियमित निगरानी से माता-पिता सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं।
5. सीखने के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करना: माता-पिता अपने बच्चे की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करके, शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके और उन्हें स्कूली पाठ्यक्रम से परे सीखने के विविध अवसरों से परिचित कराकर सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। पढ़ने को प्रोत्साहित करना, समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करना और स्कूल के बाहर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होना बच्चे के ज्ञान और रुचियों को व्यापक बना सकता है।
6. अनुशासन और मूल्य स्थापित करना: माता-पिता अपने बच्चों में अनुशासन, मूल्य और नैतिक व्यवहार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिम्मेदारी, सम्मान, दृढ़ता और सहानुभूति जैसे गुणों का पोषण करके, माता-पिता अपने बच्चे के समग्र विकास में योगदान देते हैं, जो उनकी शैक्षिक यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

7. शिक्षा के लिए वकालत: माता-पिता स्कूल और सामुदायिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व की वकालत कर सकते हैं। वे अन्य अभिभावकों के साथ सहयोग कर सकते हैं, अभिभावक-शिक्षक संघों में भाग ले सकते हैं, और शिक्षा नीतियों, बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार के लिए चर्चा और पहल में शामिल हो सकते हैं।[8,9]

अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेकर और सहायक शिक्षण माहौल को बढ़ावा देकर, माता-पिता भारतीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी भागीदारी, शिक्षकों के साथ सहयोग और उनके बच्चे की शैक्षिक यात्रा के प्रति प्रतिबद्धता उनकी शैक्षणिक उपलब्धि और समग्र विकास को प्रभावित कर सकती है।

जब माता-पिता अशिक्षित, आर्थिक रूप से वंचित होते हैं और उनकी कार्य प्रतिबद्धताएं होती हैं, तो अपने बच्चे की शिक्षा में सीधे योगदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। हालांकि, अभी भी ऐसे तरीके हैं जिनसे वे अपनी परिस्थितियों के बावजूद अपने बच्चे की शिक्षा का समर्थन कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं:

1. शिक्षा को प्राथमिकता दें: भले ही माता-पिता के पास सीमित संसाधन हों और विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़े, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे शिक्षा को प्राथमिकता दें और अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए संवाद करें और प्रोत्साहित करें और अपने होमवर्क असाइनमेंट को पूरा करने से सीखने की नींव बनाने में मदद मिल सकती है।
2. सामुदायिक सहायता लें: माता-पिता सामुदायिक संगठनों, गैर-लाभकारी समूहों या स्थानीय सरकार की पहल से संपर्क कर सकते हैं जो वंचित परिवारों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करते हैं। ये संगठन स्कूल के बाद के कार्यक्रम, ट्यूशन सेवाएं या शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच की पेशकश कर सकते हैं। ऐसी सहायता प्रणालियों से जुड़ने से शैक्षिक अवसरों में अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है।
3. स्कूल से जुड़े रहें: माता-पिता अपने बच्चे की प्रगति और उनके सामने आने वाली किसी भी चुनौती के बारे में सूचित रहने के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों के साथ नियमित संचार बनाए रख सकते हैं। माता-पिता-शिक्षक बैठकों में भाग लेना, अपने बच्चे के प्रदर्शन के बारे में अपडेट प्राप्त करना और उनकी शिक्षा में सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने से माता-पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल रहने में मदद मिल सकती है।
4. शिक्षकों के साथ सहयोग करें: माता-पिता अपने बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने और घर पर सीखने में सहायता के लिए रणनीतियों का पता लगाने के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। शिक्षक मार्गदर्शन कर सकते हैं कि माता-पिता अपने बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकते हैं, शैक्षिक गतिविधियों के लिए सुझाव दे सकते हैं और ऐसे संसाधन प्रदान कर सकते हैं जिनका उपयोग घर पर किया जा सकता है।
5. उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें: माता-पिता अपने बच्चे के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने समुदाय के भीतर या ऑनलाइन मौजूदा संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र और ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्म अक्सर पुस्तकों, शैक्षिक सामग्रियों और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करते हैं। माता-पिता इन संसाधनों का उपयोग अपने बच्चे की शिक्षा में सहायता के लिए कर सकते हैं।
6. सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दें: भले ही माता-पिता सहायता प्रदान नहीं कर सकते, फिर भी वे अपने बच्चों में सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, प्रश्न पूछना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली बातचीत में शामिल होना बच्चे के बौद्धिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। एक ऐसा घरेलू वातावरण बनाना जो शिक्षा और सीखने को महत्व देता है, उनके बच्चे की शैक्षिक यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
7. विस्तारित परिवार के साथ सहयोग करें: ऐसे मामलों में जहां माता-पिता कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वे विस्तारित परिवार के सदस्यों या विश्वसनीय व्यक्तियों से सहायता मांग सकते हैं जो उनके बच्चे की पढ़ाई की निगरानी करने, होमवर्क पूरा करने को सुनिश्चित करने या जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं।

यह देखा जा सकता है कि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक परिवार की परिस्थितियाँ अद्वितीय हैं, और सभी सुझाव हर स्थिति में लागू नहीं हो सकते हैं। हालांकि, शिक्षा को महत्व देकर, उपलब्ध संसाधनों की तलाश करके, स्कूल से जुड़े रहकर और एक सहायक घरेलू माहौल को बढ़ावा देकर, माता-पिता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने बच्चे की शैक्षिक यात्रा में बदलाव ला सकते हैं।[9,10]

स्कूल प्रबंधन समितियाँ (एसएमसी) स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एसएमसी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जिनमें माता-पिता, समुदाय के सदस्य और स्कूल स्टाफ शामिल हैं, जिन्हें स्कूल प्रशासन को बढ़ाने और शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया है। यहां एसएमसी की कुछ प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी गई हैं:

- सामुदायिक भागीदारी: एसएमसी स्कूल मामलों में सामुदायिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं। वे माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को स्कूल के कामकाज और शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित अपनी राय, चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह भागीदारी सुनिश्चित करती है कि निर्णय समुदाय के परामर्श से लिए जाएं और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें।

- स्कूल योजना और निगरानी: एसएमसी स्कूल विकास योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में शामिल हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं। एसएमसी सदस्य इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, और वे वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहराते हैं।
- संसाधन जुटाना: एसएमसी स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने में भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक धन, बुनियादी ढांचे में सुधार, शैक्षिक सामग्री और अन्य संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करते हैं। एसएमसी सरकारी प्रावधानों के पूरक के लिए सामुदायिक योगदान और स्वयंसेवा को भी बढ़ावा देते हैं।
- शिक्षक और कर्मचारी सहायता: एसएमसी शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यावसायिक विकास के अवसरों की वकालत कर सकते हैं और आवश्यक शिक्षण संसाधन प्रदान कर सकते हैं। एसएमसी शिक्षकों के लिए अनुकूल और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाते हैं, जो अंततः शिक्षण गुणवत्ता में सुधार में योगदान देता है।
- छात्र कल्याण: एसएमसी छात्रों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक सुरक्षित और समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों की वकालत कर सकते हैं, जैसे-धमकाने वाली नीतियों को लागू करना, बाल संरक्षण तंत्र को बढ़ावा देना और हाशिए पर या कमजोर छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करना। एसएमसी पाठ्येतर गतिविधियों, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहल का भी समर्थन कर सकते हैं जो समग्र विकास में योगदान करते हैं।
- सामाजिक जवाबदेही: एसएमसी स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। वे समुदाय के साथ स्कूल की नीतियों, बजट और शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी साझा करने को प्रोत्साहित करते हैं। एसएमसी शिकायतों के समाधान और स्कूल प्रबंधन में सुधार के लिए फीडबैक और शिकायतों के लिए तंत्र की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।
- स्कूल-समुदाय सहयोग: एसएमसी स्कूल और समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वे छात्रों को अतिरिक्त सहायता, सलाह या करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थानीय संगठनों, व्यवसायों और पेशेवरों के साथ साझेदारी की सुविधा प्रदान करते हैं। सामुदायिक संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, एसएमसी समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाते हैं और छात्रों के लिए अवसरों को व्यापक बनाते हैं।[10,11]

शिक्षा प्रणाली में विकेंद्रीकृत शासन और सामुदायिक भागीदारी के लिए एसएमसी आवश्यक हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, संसाधन जुटाने, स्कूल के प्रदर्शन की निगरानी करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत करने में सक्रिय रूप से शामिल होकर, एसएमसी स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

हां, शाला सिद्धि जैसे कार्यक्रम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। शाला सिद्धि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की गुणवत्ता का आकलन और सुधार करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह स्कूल स्तर पर स्व-मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और सुधार योजना के लिए एक रूपरेखा और उपकरण प्रदान करता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे शाला सिद्धि गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है:

1. स्व-मूल्यांकन: शाला सिद्धि स्कूलों को शैक्षणिक प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे, शिक्षण-सीखने की प्रक्रियाओं, सामुदायिक भागीदारी और छात्र सहायता प्रणालियों सहित विभिन्न डोमेन का स्व-मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह स्व-मूल्यांकन स्कूलों को ताकत, कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।
2. क्षमता निर्माण: शाला सिद्धि शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करती है। यह उन्हें प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को लागू करने, स्कूल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने और सीखने के माहौल को बढ़ाने के लिए तैयार करता है।
3. डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण: कार्यक्रम निर्णय-निर्माण में डेटा के महत्व पर जोर देता है। यह स्कूलों को छात्रों के प्रदर्शन, उपस्थिति, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण स्कूलों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, लक्ष्य निर्धारित करने और समय के साथ प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है।
4. सुधार योजना: शाला सिद्धि स्कूलों को उनके स्व-मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर व्यापक सुधार योजनाएं विकसित करने में मार्गदर्शन करती है। ये योजनाएँ पहचानी गई कमजोरियों को दूर करने और स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्रवाइयों, समयसीमा और संसाधन आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करती हैं। कार्यक्रम स्कूलों को योजना प्रक्रिया में शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
5. निगरानी और समीक्षा: शाला सिद्धि सुधार प्रयासों की नियमित निगरानी और समीक्षा के महत्व पर जोर देती है। यह स्कूलों को चल रही निगरानी, प्रगति पर नज़र रखने और कार्यान्वित हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सिस्टम स्थापित करने में मदद करता है। यह निरंतर समीक्षा प्रक्रिया स्कूलों को आवश्यक समायोजन करने और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

6. सामुदायिक भागीदारी: शाला सिद्धि स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को मान्यता देती है। कार्यक्रम स्कूलों को माता-पिता, स्थानीय समुदायों और हितधारकों को स्कूल की गतिविधियों, निर्णय लेने और निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सहयोग स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है, जवाबदेही को मजबूत करता है और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है।

जबकि शाला सिद्धि एक रूपरेखा और दिशानिर्देश प्रदान करती है, इसकी प्रभावशीलता अंततः स्कूल स्तर पर कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। जो स्कूल सक्रिय रूप से स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, सुधार योजना को प्राथमिकता देते हैं और तदनुसार संसाधनों का आवंटन करते हैं, उन्हें बढ़ी हुई शिक्षा गुणवत्ता के संबंध में सकारात्मक परिणाम देखने की अधिक संभावना होती है। स्कूल की गुणवत्ता में सुधार लाने में कार्यक्रम की सफलता के लिए निरंतर निगरानी, शैक्षिक अधिकारियों से समर्थन और सुधार के लिए निरंतर प्रतिबद्धता आवश्यक है।[11,12]

निष्कर्ष

हां, सभी स्कूल शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। शाला सिद्धि का कार्यान्वयन भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। हालांकि कार्यक्रम का लक्ष्य अधिक से अधिक स्कूलों तक पहुँचना है, लेकिन संसाधन की कमी, विशिष्ट क्षेत्रों की प्राथमिकता और कार्यान्वयन चुनौतियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण कवरेज सीमित हो सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शाला सिद्धि भारत में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से एक है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कार्यक्रम, नीतियाँ और हस्तक्षेप स्कूल की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य रखते हैं। ये पहल शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल शिक्षा या सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार मानती है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों से परे एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें नीतिगत सुधार, बजट आवंटन में वृद्धि और शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण को बढ़ाने की पहल शामिल है। सरकार सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बीच अंतर को पाटने पर भी काम कर रही है।

जबकि शाला सिद्धि की कवरेज के संबंध में अपनी सीमाएं हैं, यह भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक ढांचे का हिस्सा है। सरकार ऐसे कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने और सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीतियों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

समापन टिप्पणियाँ

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है। देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों में शामिल हैं:

1. बुनियादी ढाँचा: भारत में कई स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और स्वच्छता सुविधाओं जैसे बुनियादी ढाँचे का अभाव है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा समग्र शिक्षण वातावरण को बाधित करता है और शैक्षिक अवसरों को सीमित करता है।
2. शिक्षक गुणवत्ता और प्रशिक्षण: शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करने में शिक्षण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। हालाँकि प्रणाली में कई समर्पित और कुशल शिक्षक हैं, फिर भी सुसंगत और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए अपने शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने और आधुनिक शिक्षण विधियों से अपडेट रहने के लिए चल रहे व्यावसायिक विकास के अवसर, सलाह और समर्थन आवश्यक हैं।
3. पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र: पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को छात्र-केंद्रित, आकर्षक और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। रटकर याद करने से दूर जाने और आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, रचनात्मकता और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने का महत्व बढ़ रहा है।
4. मूल्यांकन एवं मूल्यांकन: मूल्यांकन प्रणाली व्यापक, निष्पक्ष और सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। निरंतर मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और फीडबैक पर ध्यान केंद्रित करने से सीखने के अंतराल की पहचान करने और छात्रों के लिए समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद मिल सकती है। परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से समग्र मूल्यांकन विधियों में बदलाव आवश्यक है।
5. समानता और समावेशन: सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग, जाति या विकलांगताओं की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
6. माता-पिता और समुदाय की सहभागिता: माता-पिता और समुदाय शिक्षा की गुणवत्ता को समर्थन और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी और शिक्षकों के साथ सहयोग छात्रों के शैक्षिक परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।[13]



शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार ने विभिन्न पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं, डिजिटल शिक्षण पहल और सामुदायिक सहभागिता रणनीतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए बड़े हुए बजट आवंटन, नीति सुधार और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हालाँकि, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार प्राप्त करने के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय सहित सभी हितधारकों से बहुआयामी दृष्टिकोण और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

- 1) Ball, A.F. (2009) 'Toward a theory of generative change in culturally and linguistically complex classrooms', *American Educational Research Journal*, vol. 46, no. 1, pp. 45–72.
- 2) Borko, H. (2004) 'Professional development and teacher learning: mapping the terrain', *Educational Researcher*, vol. 33, no. 8. Available from: http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/Volume_33_No_8/02_ERv33n8_Borko.pdf (accessed 30 July 2014).
- 3) Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2000) *Research Methods in Education*. London: RoutledgeFalmer.
- 4) Day, C. (1993) 'reflection: a necessary but not sufficient condition for professional development', *British Educational Research Journal*, vol. 19, no. 1, pp. 83–93.
- 5) Eraut, M. (2004) 'Informal learning in the workplace', *Studies in Continuing Education*, vol. 26, no. 2, pp. 247–73.
- 6) Goldacre, B. (2013) 'Building evidence into education' (online), March. Available from: <http://dera.ioe.ac.uk/17530/1/ben%20goldacre%20paper.pdf> (accessed 20 November 2014).
- 7) Haigh, N. (2005) 'Everyday conversation as a context for professional learning and development', *International Journal for Academic Development*, vol. 10, no. 1.
- 8) Hudson, P., Usak, M. and Savran-Gencer, A. (2013) 'Employing the five-factor mentoring instrument: analysing mentoring practices for teaching primary science', *European Journal of Teacher Education*, vol. 32, no. 1, pp. 63–74.
- 9) Learning to teach: an introduction to classroom research, Open University OpenLearn unit. Available from: <http://www.open.edu/openlearn/education/learning-teach-introduction-classroom-research/content-section-0> (accessed 22 October 2014).
- 10) National Council of Educational Research and Training (2005) *National Curriculum Framework*, National Council of Educational Research and Training. Available from: <http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf> (accessed 25 September 2014).
- 11) National University of Educational Planning and Administration (2014) *National Programme Design and Curriculum Framework*. New Delhi: NUEPA. Available from: https://xa.yimg.com/kq/groups/15368656/276075002/name/SLDP_Framework_Text_NCSL_NUEPA.pdf (accessed 14 October 2014).
- 12) Ulvik, M. and Sunde, E. (2013) 'The impact of mentor education: does mentor education matter.', *Professional Development in Education*, vol. 39, no. 5, pp. 754–70.
- 13) Zwart, R.C., Wubbels, T., Bergena, T.C.M. and Bolhuis, S. (2007) 'Experienced teacher learning within the context of reciprocal peer coaching', *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, vol. 13, no. 2, pp. 165–87. Available from: http://expertisecentrumlerenvandocenten.nl/files/TTTP_collegiale_coaching_0.pdf (accessed 2 August 2014).



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com